संक्षिप्त खबरें

दाम बढ़ाएगी टाटा मोटर्स

नई दिल्ली। घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स अप्रैल से अपने वाणिज्यिक वाहनों की कीमतों में दो प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में यह घोषणा करते हुए कहा कि उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के असर को कम करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। यह मूल्यवृद्धि एक अप्रैल, 2024 से लागू होगी। टाटा मोटर्स ने कहा कि वाणिज्यिक वाहनों की कीमतों में दो प्रतिशत तक की वृद्धि उनके मॉडल एवं संस्करणों के आधार पर अलग-अलग होगी। टाटा समूह की कंपनी देश में ट्रक एवं बस समेत कई तरह के वाणिज्यिक वाहन बनाती है।

ऑनर चॉइस वॉच की सेल

नई दिल्ली। ऑनर ने अपनी एआईओटी डिवाइसेज़ में नई स्मार्टवॉच - ऑनर चॉइस वॉच पेश की है, जिसकी बिक्री ब्रांड की वेबसाइट अमेज़न.इन और आपके नजदीकी मेनलाइन स्टोर्स पर शुरू होगी। ब्लैक और व्हाइट कलर वैरिएंट्स में लांच की गई इस घड़ी का मूल्य 6,499 रुपये है, जो 500 रुपये के इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट के साथ केवल 5,999 रुपये में खरीदी जा सकती है। एचटेक के सीनियर वीपी एवं ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, सीपी खंडेलवाल ने कहा, 'हम ऑनर चॉइस वॉच पेश करके उत्साहित हैं। यह एक स्टाइलिश वियरेबल डिवाइस है।

एबी ग्रुप की नई पहल

नई दिल्ली। आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट की उजास पहल मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अपने मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उजास की संस्थापक सुश्री अद्वैतेशा बिड़ला के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, यह पहल उत्तर प्रदेश राज्य में सकारात्मक बदलाव और सशक्तिकरण लाने के लिए तैयार है। प्रतिष्ठित स्थानीय एनजीओ पार्टनर ग्लैड भारत फाउंडेशन के साथ सहयोग से उजास ने किशोर लड़कियों और महिलाओं तक व्यापक रूप से पहुंच बनाने के लिए अपनी भागीदारी का पहला चरण शुरू कर दिया है। यह रणनीतिक साझेदारी एक साल तक चलने वाले अभियान की शुरुआत का प्रतीक है,।

सेंसेक्स 33 अंक चढ़ा

मुंबई। शेयर बाजारों में तेजी लगातार दूसरे दिन भी जारी रही और सेंसेक्स एवं एनएसई निफ्टी नये शिखर पर पहुंच गए। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 33.40 अंक यानी 0.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ नए रिकार्ड स्तर 74,119.39 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 159.18 अंक चढ़ गया था। पचास शेयरों पर आधारित नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 19.50 अंक यानी 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,493.55 अंक के नए रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ।(एजेंसियां)

काम और जिंदगी के बीच संतुलन महिलाओं के करियर की सबसे बड़ी बाधा

नई दिल्ली (भाषा)। कामकाज और निजी जिंदगी के बीच संतुलन महिलाओं के लिए करियर में आगे बढ़ने की राह में एक बड़ी बाधा है। एक सर्वेक्षण से यह नतीजा निकला है।

शिक्षा-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप 'हीरो वायर्ड' की तरफ से कराए गए इस सर्वेक्षण के मुताबिक, 70 प्रतिशत लोगों का मानना है कि महिलाओं के लिए काम एवं जिंदगी के बीच संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इससे महिलाओं का करियर विकास भी प्रभावित होता है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 77 प्रतिशत प्रतिभागियों का मत है कि पिछले वर्षों की तुलना में नेतृत्व वाले पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। हीरो वायर्ड ने एक विज्ञप्ति में कहा कि 'भारत में आधुनिक कार्यस्थलों में महिलाएं' शीर्षक रिपोर्ट को दो लाख महिलाओं के बीच कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष

यह सर्वेक्षण आठ मार्च को मनाए जाने वाले 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' से पहले आया है।

इस रिपोर्ट में एक अंतराल के बाद काम पर लौटने वाली महिलाओं को पेश आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट कहती है, 'इन महिलाओं के लिए संपर्क से बाहर महसूस करना, कौशल में गिरावट को लेकर चिंता और नौकरी के उपयुक्त अवसर तलाशने में परेशानियां जैसे कारक बड़ी बाधाएं बनकर उभरते हैं।' रिपोर्ट के मुताबिक, करियर में दोबारा सहज होने और आगे बढ़ने की इच्छा के बावजूद ये चुनौतियां अक्सर महिलाओं को कार्यस्थल में अपनी क्षमता का पूरी तरह लाभ उठाने से रोकती हैं।

हालांकि 59 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि आज के कार्यबल में महिलाओं के पास पुरुषों के समान अवसर हैं, जो कार्यस्थल समानता की दिशा में बदलती गतिशीलता को दर्शाता है। इसके अलावा, 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नेतृत्व पदों पर अधिक महिलाओं की मौजूदगी से होने वाले लाभ को स्वीकार किया। उनका मानना है कि यह कार्यस्थल संस्कृति में विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने में योगदान देता है।

हीरो वायर्ड के सीईओ अक्षय मुंजाल ने कहा कि महिला कर्मचारियों के लिए मददगार माहौल को बढ़ावा देने, पूर्वाग्रहों को दूर करने और पेशेवर विकास के लिए अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासों की जरूरत है।

अब आर्थिक कानूनों में भी बदलाव की जरूरत : वैष्णव

नई दिल्ली (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत को अपनी वृद्धि की जरूरतों को देखते हुए आर्थिक कानूनों में बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने औपनिवेशक दौर के कानूनों की जगह लेने के लिए बनाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों का जिक्र करते हुए बृहस्पतिवार को यह बात कही।

सरकारी शोध संस्थान नीति आयोग के एक कार्यक्रम में वैष्णव ने कहा कि देश भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के साथ आपराधिक न्यायशास्त्र में बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। इन तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसम्बर को संसद की मंजूरी मिली थी जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसम्बर को इन्हें मंजूरी दी थी। ये तीनों कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेंगे। संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णव ने कहा, 'इन कानूनों की तरह हमारी मौजूदा आवश्यकताओं और वृद्धि की जरूरतों को देखते हुए आर्थिक कानूनों में भी बदलाव की जरूरत है।'

उन्होंने कहा, 'अगर आप 2,000 अच्छे वकीलों की सेवाएं लेते हैं तो आप अगले पांच वर्षों में लगभग 35,000 कानूनों में सुधार कर सकते हैं।' वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक ध्यान देगी क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की व्यापक क्षमता है।

नीति आयोग का डिजिटल बुनियादी ढांचा मंच शुरू

नई दिल्ली (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मंच 'नीति फॉर स्टेट्स' की शुरुआत की जो नीति और शासन के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है।

संचार, रेलवे और इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्री वैष्णव ने नीति आयोग की इमारत में 'विकसित भारत रणनीति कक्ष' का भी उद्घाटन किया। यह कक्ष प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए अंतर्दृष्टि, सूचना और ज्ञान साझा करने का काम करेगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, नीति आयोग का मंच 'नीति फॉर स्टेट्स' 7,500 सर्वोत्तम प्रथाओं, 5,000 नीतिगत दस्तावेजों, 900 से अधिक डेटासेट, 1,400 डेटा प्रोफाइल और 350 नीति प्रकाशनों का एक बहु-क्षेत्रीय सजीव भंडार होगा।

इस डिजिटल मंच पर उपलब्ध सूचनाएं 10 क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इनमें कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल, विनिर्माण, एमएसएमई, पर्यटन, शहरी मामले, जल संसाधन और जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता) शामिल हैं।

वाहन बिक्री ने भरा फर्राटा

■ फरवरी में खुदरा बिक्री में दर्ज की गई 13 फीसद की बढ़ोतरी

नई दिल्ली (भाषा)।

फरवरी में यात्री और दोपहिया वाहनों समेत सभी खंडों में तगड़ी खरीदारी आने से देश में वाहनों की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़ गई। वाहन वितरकों के संगठन फाडा ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पिछले महीने कुल 20,29,541 वाहनों की खुदरा बिक्री हुई जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 17,94,866 इकाई थी। यात्री वाहन खंड में पिछले महीने बिक्री 12 प्रतिशत बढ़कर 3,30,107 इकाई हो गई, जो फरवरी, 2023 में 2,93,803 इकाई थी। 'फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन' (फाडा) के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने एक बयान में कहा, 'फरवरी के महीने में यात्री वाहनों की अब तक की सर्वाधिक बिक्री दर्ज की गई। नए उत्पादों की रणनीतिक पेशकश और वाहनों की उपलब्धता बढ़ने की इसमें अहम भूमिका रही।'

पिछले महीने दोपहिया वाहनों की बिक्री 13 प्रतिशत बढ़कर 14,39,523 इकाई रही, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 12,71,073 इकाई थी। सिंघानिया ने कहा कि दोपहिया वाहन खंड में वृद्धि के पीछे ग्रामीण क्षेत्र की मांग, प्रीमियम माडलों की चाहत, व्यापक उत्पाद उपलब्धता और दिलचस्प ऑफर की अहम भूमिका रही। उन्होंने कहा कि शादियों के मौसम और बेहतर आर्थिक स्थिति जैसे कारकों ने भी इस सकारात्मक वृद्धि में योगदान दिया।

■ यात्री वाहन खंड की बिक्री में 12 फीसद तक की वृद्धि
■ दुपहिया की बिक्री में दर्ज की गई 13 फीसद की बढ़ोतरी

फरवरी में वाणिज्यिक वाहनों की खुदरा बिक्री बढ़कर 88,367 इकाई हो गई, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक है। सिंघानिया ने कहा कि नकदी प्रवाह की कमी और चुनाव से संबंधित खरीद स्थगन जैसी बाओं के बावजूद इस खंड में वृद्धि देखी गई, जो इस क्षेत्र के लचीलेपन और क्रमिक सुधार को उजागर करती है।

तिपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री भी पिछले महीने 24 प्रतिशत बढकर 94,918 इकाई हो गई। इसी तरह, ट्रैक्टर की बिक्री 11 प्रतिशत बढकर 76,626 इकाई हो गई।

फेम की समयसीमा नहीं बढ़ेगी

नई दिल्ली (भाषा)।

सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की प्रमुख योजना फेम के दूसरे चरण को 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम दो योजना की समयावधि बढ़ाए जाने को लेकर मीडिया रिपोर्ट में किए गए दावे का खंडन किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र ने 500 करोड़ रुपये के व्यय के साथ योजना को 31 जुलाई तक अस्थायी रूप से चार महीने के लिए बढ़ा दिया है।

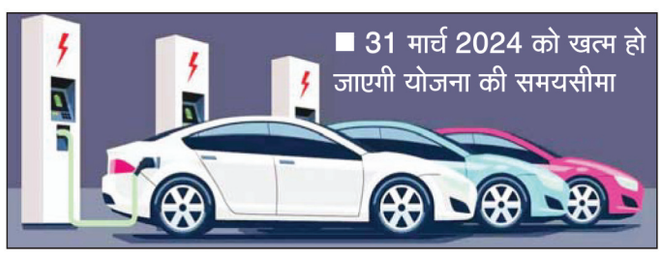

■ 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगी योजना की समयसीमा

भारी उद्योग मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि फेम योजना के दूसरे चरण के तहत सब्सिडी 31 मार्च, 2024 तक या धन उपलब्ध होने तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों के लिए मिलेगी। उसने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता और विनिर्माण में तेजी (फेम-दो) कार्यक्रम के लिए व्यय 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

मंत्रालय ने बयान में कहा था कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजना का दूसरा चरण... फेम दो कोष और अवधि के लिहाज से सीमित समय के लिए है।

संशोधित व्यय के अनुसार इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया और इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहन 7,048 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ उठाने के पात्र हैं। इसके अलावा, पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में 4,048 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि 400 करोड़ रुपये 'अन्य' श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं।

अमित शाह आज जारी करेंगे राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस

नई दिल्ली (भाषा)।

सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सहकारिता केंद्रित आर्थिक माडल के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस जारी करेंगे।

बृहस्पतिवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, शाह 'राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस', 2023 पर एक रिपोर्ट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण 'सहकार से समृद्धि' को पूरा करने के लिए यह सहकारिता मंत्रालय का एक और महत्वपूर्ण कदम है।

इस पहल के तहत, सहकारिता मंत्रालय ने देश के विशाल सहकारी क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए एक मजबूत 'डाटाबेस' की जरूरत को पहचाना है।

घरेलू मुद्रा में ट्रेड करेंगे इंडोनेशिया और भारत

■ आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया में हुआ करार

मुंबई (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया (बीआई) ने बृहस्पतिवार को द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये।

आरबीआई ने बयान में कहा कि सीमापार लेनदेन के लिए भारतीय रुपये और इंडोनेशियाई रुपैया (आईडीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने को लेकर व्यवस्था बनाने के लिए यहां समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह व्यवस्था निर्यातकों और आयातकों को संबंधित घरेलू मुद्राओं में बिल भुगतान करने की सुविधा देगी। इससे रुपया और इंडोनेशियाई मुद्रा के विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार के विकास में मदद मिलेगी।

आरबीआई ने कहा, 'स्थानीय मुद्राओं के उपयोग से लेनदेन की लागत और निपटान समय कम होगा।' एमओयू पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारजियो ने हस्ताक्षर किये।

आरबीआई ने कहा, 'समझौता ज्ञापन का उद्देश्य द्विपक्षीय रूप से रुपया और आईडीआर के उपयोग को बढ़ावा देना है।' केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह सहयोग आरबीआई और बीआई के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसमें कहा गया है कि द्विपक्षीय लेनदेन में स्थानीय मुद्राओं का उपयोग अंततः भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय एकीकरण तथा आपसी लंबे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंधों को मजबूती करने में योगदान देगा।

सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में आदिवासियों को ट्रेनिंग

नई दिल्ली (भाषा)।

भारतीय विज्ञान संस्थान के सहयोग से आदिवासी छात्रों को सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ मिलकर दूरदराज के आदिवासी गांवों में मोबाइल और इंटरनेट संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पायलट आधार पर उपग्रह-आधारित तकनीक का उपयोग करने की भी योजना बना रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) शुरू किया है। इसको देखते हुए आने वाले वर्षों में सेमीकंडक्टर उद्योग में नौकरियों की काफी संभावनाएं हैं।

सितम्बर तक सुस्त रहेगी एफएमसीजी क्षेत्र की वृद्धि

नई दिल्ली (भाषा)।

रोजमर्रा के उपभोग वाले उत्पाद (एफएमसीजी) क्षेत्र में अनिश्चित कारोबारी परिदृश्य की वजह से इस साल सितम्बर तिमाही तक 'धीमी' रफ्तार से वृद्धि होने का अनुमान है।

डेटा एवं सलाहकार फर्म कांतार वर्ल्डपैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता बनी रहने से मांग पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा आगामी आम चुनावों से भी एफएमसीजी उत्पादों की खपत बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही है।

हालांकि, कांतार ने उम्मीद जताई है कि सितम्बर तिमाही के बाद एफएमसीजी क्षेत्र की वृद्धि 'उत्तरोत्तर' बेहतर होगी। दूसरी छमाही में रबी की अच्छी फसल होने पर यह साल भी अच्छा साबित हो सकता है।

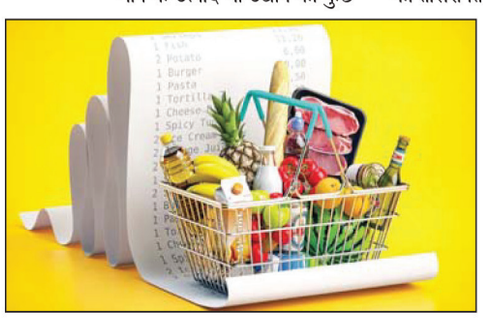

रिपोर्ट कहती है कि गर्मियों से संबंधित कुछ श्रेणियों और कपड़े धोने के उत्पाद भी उद्योग को कुछ हद तक समर्थन देंगे। हालांकि, इन श्रेणियों में संयुक्त वृद्धि का समग्र एफएमसीजी पर प्रभाव नगण्य ही रहेगा। ऐसी स्थिति में साल 2024 की तीसरी तिमाही तक एफएमसीजी की वृद्धि कम होने का अनुमान है। पिछले साल की पहली छमाही के मजबूत प्रदर्शन की वजह से इस साल की पहली छमाही में एफएमसीजी की वृद्धि स्थिर भी रह सकती है। हालांकि, उसके बाद हालात धीरे-धीरे बेहतर होते जाएंगे।

जहां तक 2024 के चुनावी साल होने से मांग बढ़ने की संभावना का सवाल है तो इस रिपोर्ट में इससे इनकार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चुनावी वर्षों में एफएमसीजी में कोई उछाल नहीं देखा गया था। मुफ्त सुविधाओं की घोषणा से बिक्री में ठहराव या संकुचन ही रहा था।

रिपोर्ट के मुताबिक, चुनावी साल 2009 में उपभोग वृद्धि 0.7 प्रतिशत थी जबकि 2014 में यह स्थिर थी और 2019 के साल में यह नकारात्मक रही थी।

पाक का बाह्य ऋण बढ़ा

इस्लामाबाद (भाषा)। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान का विदेशी सार्वजनिक ऋण पिछले साल अप्रैल-सितम्बर की अवधि में 1.2 अरब डालर बढ़कर 86.35 अरब डालर से अधिक हो गया जिसमें विश्व बैंक और चीन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही। आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए विदेशी आर्थिक मदद पर जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक, पाकिस्तान को जुलाई-सितम्बर, 2023 में 1.5 अरब डालर के ऋण भुगतान के मुकाबले 3.5 अरब डालर का कुल विदेशी धन मिला जिससे शुद्ध प्रवाह 1.97 अरब डालर का रहा।

सितम्बर, 2023 तक पाकिस्तान सरकार का कुल बाहरी सार्वजनिक ऋण बढकर 86.35 अरब डालर हो गया। मंत्रालय के हवाले से समाचारपत्र 'द डान' में बृहस्पतिवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुल बाहरी सार्वजनिक ऋण का लगभग 64 प्रतिशत रियायती शर्तों और लंबी परिपक्वता अवधि वाले बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्रोतों से मिला था। पाकिस्तान पर मार्च, 2023 तक बाह्य सार्वजनिक ऋण 85.18 अरब डालर था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 64.2 करोड़ डालर के नए ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे और सभी नई प्रतिबद्धताओं को बहुपक्षीय विकास भागीदारों द्वारा वित्तपोषित किया गया था।

मुक्का प्रोटीन्स का शेयर 51 प्रतिशत तक चढ़ा

नई दिल्ली (भाषा)।

मछली का तेल और संबद्ध उत्पादों के विनिर्माण एवं विपणन से जुड़ी कंपनी मुक्का प्रोटीन्स का शेयर बृहस्पतिवार को सूचीबद्धता के दिन निर्गम मूल्य के मुकाबले 51 प्रतिशत की बढत लेने में सफल रहा।

बीएसई पर मुक्का प्रोटीन्स ने 57.14 प्रतिशत की बढ़त के साथ 44 रुपये के भाव पर कारोबार की शुरुआत की। हालांकि, बाद में यह थोड़ा नरम पड़कर 42.26 रुपये पर आ गया, जो 28 रुपये के निर्गम मूल्य से 50.92 प्रतिशत अधिक है।

एनएसई पर भी कंपनी का शेयर निर्गम मूल्य से 42.85 प्रतिशत की बढ़त के साथ 40 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ था। बाद में यह तेजी से ऊपर की ओर भागते हुए 42.25 रुपये के भाव तक पहुंच गया जो 50.89 प्रतिशत का उछाल है।

दफ्तर से काम पर जोर देने से महिलाओं की संख्या घटी

मुंबई (भाषा)।

दफ्तर से काम को बड़े पैमाने पर प्राथमिकता दिए जाने के बाद से कंपनियों में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर महिलाओं की मौजूदगी घट गई है। एक रिपोर्ट में बृहस्पतिवार को यह आकलन पेश किया गया।

सलाहकार फर्म ग्रांट थॉर्नटन इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लगातार तीसरे साल कार्यस्थलों पर विविधता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक मानी जाने वाली वरिष्ठ प्रबंधन भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी कम हुई है। लगभग चार साल पहले कोविड महामारी की शुरुआत ने घर से काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया था। इससे सभी श्रमिकों के लिए कामकाजी परिवेश बेहद लचीला बन गया था और मुश्किल दौर में भी महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बनी रही। लेकिन महामारी का प्रकोप खत्म होने के बाद कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को दोबारा कार्यालय बुलाना शुरू कर दिया। हालांकि, कुछ कंपनियों ने बाद में भी हाइब्रिड कामकाजी माडल को जारी रखा जिसमें कर्मचारियों को घर से भी काम करने की सुविधा मिलती है।

हालांकि, अब हाइब्रिड कामकाजी मॉडल को भी कंपनियां बंद कर रही हैं। इसका असर कार्यबल खासकर वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर महिलाओं की भागीदारी पर देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले आई यह रिपोर्ट कई कंपनियों की वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर बैठी लगभग 300 महिलाओं से मिले जवाब पर आधारित है।

सलाहकार फर्म ने कहा कि भारतीय मध्य-बाजार कंपनियों में 34 प्रतिशत महिलाएं फिलहाल वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर हैं जबकि 2023 में 36 प्रतिशत और 2022 में 38 प्रतिशत से थोड़ी कम थी। हालांकि, 34 प्रतिशत की मौजूदा हिस्सेदारी भी 2004 के 12 प्रतिशत और 2014 के 14 प्रतिशत अनुपात की तुलना में बहुत अधिक है। हाइब्रिड माडल की सुविधा देने वाली कंपनियों की संख्या पिछले साल 62.3 प्रतिशत थी लेकिन यह घटकर 2024 में 56.5 प्रतिशत रह गई। इसके उलट अपने कर्मचारियों को दफ्तर आकर काम करने के लिए कहने वाली कंपनियां 2023 के 27.4 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 34.7 प्रतिशत हो गई हैं।

इसका असर यह हुआ है कि अपने घरों से बाहर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या घटकर सिर्फ 1.8 प्रतिशत रह गई है जबकि 2023 में यह आंकड़ा 5.3 प्रतिशत था।